

Q.1. अवमूल्यन के प्रमुख उद्देश्य बताइये। किसी देश के व्यापार संतुलन में सुधार हेतु अवमूल्य किन शर्तों के अन्तर्गत लाभप्रद हो सकता है?

(Discuss the main objectives of devaluation. Under what conditions can devaluation bring about an improvement in the balance of trade of a country ?)

Or, 1996 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन क्यों किया गया? इसका भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा?

(Why was Indian Rupee devalued in June, 1966 ? How did it affect Indian Economy ?)

Ans. अवमूल्यन से आशय देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं की तुलना में मूल्य का कम करने से है। यह देश की मुद्रा की बाह्य कीमत को कम करने की एक विवेकपूर्ण नीति है जिसमें आंतरिक मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होने दिया जाता। अवमूल्यन की कुछ मुख्य परिभाषायें निम्नलिखित हैं— **पाल ऐंजिंग के अनुसार**, “मुद्राओं की अधिकृत समताओं में कमी करना अवमूल्य है।” **डॉ० गांगुली के अनुसार**, “अवमूल्यन को किसी भी देश की चलन इकाई के बाह्य मूल्यों में कमी कर देने को सरल रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

उदाहरण—यदि डॉलर का रुपये के रूप में मूल्य बढ़ा दिया जाये अथवा रुपये का मूल्य डॉलर के रूप में कम कर दिया जाये तो इसे भारतीय रुपये का अवमूल्यन कहा जायेगा।

अवमूल्यन के उद्देश्य (Objectives of Devaluation)

(i) निर्यात को प्रोत्साहन देना। (ii) आयातों को हतोत्साहित करना। (iii) विदेशी मुद्राओं की चोर-बाजारी को रोकना। (iv) अन्य देशों द्वारा राशिपातन को रोकना। (v) विदेशी निवेशकर्ताओं को पूँजी निवेश हेतु प्रोत्साहित करना।

अवमूल्यन की सफलता की शर्तें

(Conditions for the Success of Devaluation)

(1) **आयातित वस्तुओं की माँग अत्यधिक लोचदार होनी चाहिये (The Demand for the Imported Goods should be more Elastic)** : अवमूल्यन के फलस्वरूप देश के आयात तभी कम होंगे जब आयातित वस्तुओं की माँग अत्यधिक लोचदार हो।

(2) **दूसरे देशों में निर्यातित वस्तुओं की माँग भी अत्यधिक लोचदार होनी चाहिये (The Demand for Export Goods in Other Countries should be more Elastic)** : अवमूल्यन देश के प्रतिकूल भुगतान शेष को ठीक करने में तभी सहायक हो सकता है जबकि हमारी निर्यातित वस्तुओं की माँग की लोच इकाई से अधिक हो।

(3) **अवमूल्यन के साथ-साथ देश के आन्तरिक मूल्यों में परिवर्तन नहीं होना चाहिये (The internal prices should not change along with Devaluation)** : अवमूल्यन के फलस्वरूप उत्पादन लागत व मूल्यों में वृद्धि नहीं होनी चाहिये अन्यथा निर्यात में आशातीत वृद्धि नहीं होगी।

(4) **निर्यातित वस्तुओं की पूर्ति पर्याप्त होनी चाहिये (The Supply of Export)**

goods should be adequate) : अवमूल्यन के पश्चात् निर्यातों में वृद्धि तभी संभव है जब देश में वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन हो और आन्तरिक माँग की पूर्ति करने के पश्चात् पर्याप्त निर्यात योग्य अतिरिक्त उपलब्ध हो।

(5) अन्य देश अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन न करें (Other Countries should not devalue their Currency) : अवमूल्यन की सफलता के लिये यह भी आवश्यक है कि हमारे साथ-साथ वे भी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन न करें अन्यथा निर्यातों में आशानुकूल वृद्धि नहीं होगी।

(6) आयातित वस्तुओं का प्रतिस्थापन सम्भव होना चाहिये (Import substitution should be possible) : अवमूल्यन के पश्चात् उन वस्तुओं, जिनका हम विदेशों से भारी मात्रा में आयात करते रहे हैं, अपने देश में ही उत्पादन के लिये प्रयास किये जाने चाहिये।

(7) अवमूल्यन मुद्रा-स्फीति काल में न किया जाये (Currency should not be devalued during Inflation) : मुद्रा-स्फीति काल में अवमूल्यन होने पर वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि स्फीति काल में लोगों में संचय प्रवृत्ति बढ़ जाती है और निर्यात योग्य अतिरिक्त कम हो जाता है।

(8) देश की अर्थ-व्यवस्था में विदेशी व्यापार तथा पूँजी का पर्याप्त महत्व होना चाहिये (Foreign Trade and Capital should have due Importance in the Economy of Country) : अवमूल्यन का लाभ उसी देश को अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है जिसके लिये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व विदेशी निवेशों का महत्व अधिक हो।

1966 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन

(Devaluation of Indian Rupee in 1966)

राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखकर 6 जून, 1966 को वित्तमंत्री श्री शचीन चौधरी ने प्रातः 2 बजे भारतीय रुपये का 36.5% अवमूल्यन किया जिसके फलस्वरूप रुपये का स्वर्ण-मूल्य 0.118516 ग्राम और डॉलर-मूल्य 13.33 सेन्ट रह गया। इस प्रकार रुपये के मूल्य में विदेशी मुद्रा की तुलना में 36.5% की कमी हुई थी जबकि विदेशी मुद्रायें रुपये की तुलना में 57.51% अधिमूल्यित हो गयी थीं।

रुपये के अवमूल्यन के कारण

(Causes of Devaluation of Rupee)

भारतीय रुपये के अवमूल्यन बिना सोचे-समझे उठाया गया कदम नहीं था बल्कि देश की मुद्रा प्रणाली में इस प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो गयी थीं कि बिना अवमूल्यन किये उन्हें दूर नहीं किया जा सकता था। अवमूल्यन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

(1) मूल्य-स्तर में वृद्धि (Rise in Price Level) : भारतीय बाजार में गत 10 वर्षों में वस्तुओं के मूल्यों में 80% वृद्धि हो गयी थी जिसको कम करने के सभी प्रयास असफल हो गये थे। तत्कालीन वित्तमंत्री श्री शचीन चौधरी के शब्दों में, “मूल्यों को नीचे लाना संभव नहीं था।” भारतीय माल के मूल्य ऊँचे होने के कारण उसे विदेशों में बेचना कठिन हो रहा था। अतः भारतीय माल को विदेशी बाजार में सस्ता बनाने की यह अप्रत्यक्ष रीति निकाली गयी और रुपये का अवमूल्यन कर दिया गया।

(2) व्यापार-संतुलन में प्रतिकूलता (Unfavourable Balance of Payments) : भारत का व्यापार संतुलन कई वर्षों से प्रतिकूल चल रहा था जिसके कारण भारत के विदेशी मुद्रा कोष में अत्यधिक गिरावट आ गयी थी। इसे सुधारने के लिये आयातों को घटाना और

निर्यातों को प्रोत्साहित करना आवश्यक था। अतः रुपये का अवमूल्यन किया गया।

(3) निर्यात संवर्द्धन नीति की असफलता (Failure of the Policy of Export Promotion) : सरकार ने देश के निर्यात बढ़ाने के लिये अनेक उपाय (जैसे निर्यातकों को अधिक सहायता देना, निर्यातकों को कच्चे माल आदि का आयात करने में सुविधा देना, निर्यात पर करों की छूट आदि) अपनाये परन्तु सन्तोषप्रद परिणाम नहीं आये, जिससे सरकार के समक्ष अवमूल्यन ही एकमात्र उपाय रह गया था।

(4) विदेशी सहायता का अभाव (Lack of Foreign Aid) : भारत की अर्थव्यवस्था की गिरती हुई दशा के कारण विदेशों से सहायता मिलने में कठिनाई उत्पन्न हो रही थी, जिसके फलस्वरूप भारत की विकास संबंधी योजनाओं के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। अतः विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिये रुपये का अवमूल्यन किया जाना उचित समझा गया।

(5) विदेशी पूँजी के आयात को प्रोत्साहित करने व भारतीय पूँजी के निर्यात को हतोत्साहित करने के लिये (To Encourage Imports of Foreign Capital and to Discourage Exports of Indian Capital): भारतीय रुपये के अवमूल्यन का एक प्रमुख कारण स्वदेश में विदेशी पूँजी के आयात को प्रोत्साहित करना तथा स्वदेशी पूँजी को हतोत्साहित करना था जिससे एक ओर देश के आर्थिक विकास की गति तीव्र हो सके और दूसरी ओर भुगतान शेष की प्रतिकूलता तथा विदेशी विनिमय संकट दूर हो सके।

अवमूल्यन के प्रभाव (Effects of Devaluation) : भारतीय अर्थव्यवस्था पर अवमूल्यन के निम्नलिखित प्रभाव पड़े—

(1) आयातों के मूल्य में वृद्धि (Increase in the Prices of Imports) : अवमूल्यन के कारण हमारे लिये आयातों के मूल्य 57.5% बढ़ गये जिसका प्रभाव आयातों को कम करना हो गया। अवमूल्यन के पहले वर्ष में हमारे आयात 300.4 करोड़ डॉलर से घटकर 259.7 करोड़ डॉलर रह गये जिसके कारण भुगतान संतुलन में कुछ सुधार हुआ। यद्यपि अवमूल्यन से आयातों में कमी होने की प्रवृत्ति स्थापित हो गयी, तथापि अवमूल्यन ने हमारे आयातों को महँगा कर दिया जिसके कारण हमारी योजनाओं की विदेशी विनिमय की लागत बढ़ गयी।

(2) निर्यातों में गिरावट (Decline in Export) : अवमूल्यन का उद्देश्य निर्यातों को बढ़ाना था परन्तु हमारे निर्यात बढ़ने की अपेक्षा कम हो गये। अवमूल्यन के पहले वर्ष में हमारे निर्यात 171.1 करोड़ डॉलर से घटकर 150.5 करोड़ डॉलर रह गये। निर्यातों में कमी होने का मुख्य कारण विदेशों में हमारी वस्तुओं की माँग का बेलोचदार होना, घरेलू बाजार का अनाकर्षक होना तथा निर्यात के लिये पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं का उपलब्ध न होना था।

(3) कीमतों में वृद्धि (Rise in Prices) : अवमूल्यन के परिणामस्वरूप हमारे देश में कीमतों में और अधिक वृद्धि हो गयी। अवमूल्यन से पहले अप्रैल, 1966 में थोक मूल्यों का सूचकांक 176.4 था जो बढ़कर सितम्बर, 221.4 हो गया। इसके मुख्य कारण निम्न थे—(i) ऐसी वस्तुयें जिनके निर्माण में आयातित कच्चे-माल का प्रयोग होता था उनकी कीमतें बढ़ जाने से निर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गयी। (ii) निर्यात में वृद्धि से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गयी। (iii) मूल्यों में इस प्रकार की वृद्धि का प्रभाव अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर भी पड़ा। महँगाई के साथ-साथ मजदूरी व महँगाई-भत्ते में भी वृद्धि होती गयी। इस प्रकार मूल्य-वृद्धि का प्रभाव धीरे-धीरे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ गया।

(4) योजनाओं की लागतों में वृद्धि (Increase in the Cost of Plans) : अवमूल्यन

के कारण विदेशों से आने वाले पूँजीगत व कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण देश में आर्थिक विकास की योजनाओं की लागत बढ़ गयी। अधिकांश योजनाओं का विदेशी विनिमय व्यय इतना बढ़ गया कि पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता न मिलने के कारण उनको पूरा करने में कठिनाई हो गयी। परिणामतः देश के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो गयी।

(5) विदेशी सहायता महँगी (Costly Foreign Aid) : विदेशी वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से विदेशी सहायता की क्रय-शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत कम रह गई। अतः विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिये अधिक विदेशी सहायता की आवश्यकता हुई।

(6) ऋण दायित्वों में वृद्धि (Increase in Debt Liabilities) : अवमूल्यन से भारतीय रुपये का मूल्य विदेशी मुद्रा में कम हो गया है जिसके कारण अब विदेशी मुद्रा के बदले में अधिक भारतीय मुद्रा देनी होती थी। इसलिये रुपये में विदेशी ऋणों का भार पहले की अपेक्षा अधिक हो गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अवमूल्यन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। इसमें न केवल देश के निर्यात हतोत्साहित हुए, विकास की योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा बल्कि देश के आंतरिक मूल्य भी प्रभावित हुए जिसने देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया।

जुलाई, 1991 का अवमूल्यन एवं उसके प्रभाव (Devaluation of July, 1991 and its Effects)

1991 में रुपये का दो बार अवमूल्यन किया गया। प्रथम अवमूल्यन 1 जुलाई, 1991 तथा दूसरा अवमूल्यन 3 जुलाई, 1991 को किया गया। दूसरे अवमूल्यन के बाद रुपये की कीमत कुल मिलाकर 18% कम हो गयी। 3 जुलाई के पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् पौण्ड का मूल्य 41.59 रु० तथा डॉलर का मूल्य 26.95 रु० हो गया। इसी प्रकार जापानी येन व जर्मन मार्क के मूल्य में भी वृद्धि हुई।

इस प्रकार दो किशतों में किये गये अवमूल्यन के पश्चात् रुपये का मूल्य पौण्ड के मुकाबले 17.38%, डॉलर के मुकाबले 18.74%, डोयश मार्क के मुकाबले 17.21%, येन के मुकाबले 18.25% तथा फ्रांसीसी फ्रैंक के मुकाबले 17.35% गिर गया है।

तत्पश्चात् सरकार ने सामान्य 2% का अतिरिक्त अवमूल्यन करके विदेशी मुद्राओं को पुनः समायोजित किया।

वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह के अनुसार यह अवमूल्यन भुगतान संतुलन एवं विदेशी विनियोग संकट की समस्या को हल करने के लिये किया गया है किन्तु इसमें भारत का विदेशी ऋण 1310.1 अरब रुपये से बढ़कर 1620 अरब रु० हो गया है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय के मुकाबले विदेशी ऋण का अनुपात 38% से बढ़कर 47% हो गया है। आशा की गयी कि इससे आयातों में कमी होगी और निर्यातों में वृद्धि।

अवमूल्यन के कारण (Causes of Devaluation) : अवमूल्यन के प्रमुख कारण थे—

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार उपरोक्त अवमूल्यन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं की कीमतों में हुये परिवर्तनों के अनुरूप किया गया सामान्य समायोजन था, फिर भी इसके मुख्य कारण निम्नांकित थे—

1. हमारा भुगतान संतुलन निरन्तर प्रतिकूल हो गया था जिसके कारण हमारा विदेशी विनिमय कोष घटता जा रहा था। यह कोष धीरे-धीरे घटकर जुलाई, 1991 में मात्र, 2500 करोड़ रु० रह गया था, जो 11 दिन के आयात के लिये भी पर्याप्त नहीं था।

2. विदेशी व्यापार निरन्तर घाटे में था। 1990-91 में यह घाटा सर्वाधिक (10,644 करोड़ रु०) था। इसे कम करने के लिये निर्यातों को बढ़ाना आवश्यक था।

3. भारत पर विदेशी कर्ज निरन्तर बढ़ता जा रहा था। 1990-91 में कर्ज अदायगी निर्यात आय की 30 प्रतिशत हो गयी थी।

4. खाड़ी युद्ध के कारण व्यापार में लगातार बाधा पड़ रही थी।

5. पश्चिमी देशों से मिलने वाली सहायता में कमी आ गयी थी।

6. अनिवासी भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली तथा पर्यटन और अन्य सेवाओं से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा में कमी आ गयी थी।

अवमूल्यन के सम्भावित परिणाम

(Probable Effects of Devaluation)

अवमूल्यन के सम्भावित परिणाम निम्न प्रकार आँके गये थे—

1. अवमूल्यन से हमारे निर्यातों में वृद्धि होगी।

2. आयात 20 से 22 प्रतिशत महँगे हो जायेंगे। आयात घटने से प्रयुक्त आय कम होगी।

3. विदेशी ऋण 1130 अरब रुपये से बढ़कर 1620 अरब रु० हो जायेगा। इसी अनुपात में हमारे ब्याज व अन्य भुगतान भी बढ़ जायेंगे।

4. अर्थव्यवस्था में स्फीतिक शक्तियाँ बलवती हो जायेंगी।

वास्तव में जुलाई, 1991 का अवमूल्यन वर्तमान में व्याप्त विदेशी मुद्रा संकट को टालने के लिये किया गया था। फिर, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी भारत पर जबर्दस्त दबाव था।